



सत्यमेव जयते

::आयुक्त (अपील-II) का कार्यालय,केंद्रीय उत्पाद

शुल्कः:

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS-II), CENTRAL EXCISE,
7th मंजिल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, 7th Floor, Central Excise
पोलिटैकनिक के पास, Building,
आम्बवाडी, अहमदाबाद : 380015 Near Polytechnic,
Ambavadi,
Ahmedabad:380015



रजिस्टर डाक ए .डी .द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2(84) 23/Ahd-II/Appeals-II/ 2015-16 /1714 जो 1718
स्थगन आवेदन संख्या(Stay App. No.):

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP- 034 -16-17

दिनांक (Date): 26.08.2016, जारी करने की तारीख (Date of issue): 06/09/16

श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker , Commissioner (Appeals-II)

ग _____ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-II), अहमदाबाद- II, आयुक्तालय द्वारा जारी

मूल आदेश सं _____ दिनांक _____ से सृजित

Arising out of Order-In-Original No. MP/07/Dem/AC/2015/AP Dated: 13-03-2015
issued by: Assistant Commissioner., Central Excise (Div-II), Ahmedabad-II

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Dhall Enterprises & Engineering Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए ।

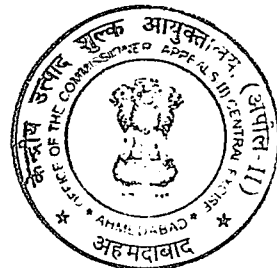
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो ।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है ।

U. J. J.



Cont...2

- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, Under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं
- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.
- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.
- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के ऑफिस में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।



रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-; Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

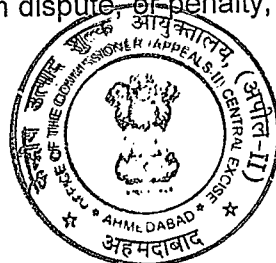
For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER IN APPEAL

The subject appeal is filed by M/S. Dhall Enterprises & Engineers Pvt. Ltd., sijpur Bogha, Near G.D. High school, Naroda Road, Ahmedabad-382345(herein after referred to as "the Appellant") against OIO No No.MP/07/DEM/AC/2015/AP Dtd. 13/3/2015(hereinafter referred to as 'the impugned order) Passed By The Assistant Commissioner,CentralExcise, Division-II,Ahmedabad-II,(hereinafter referred to as 'the adjudicating authority') engaged in the manufacture of Excisable goods falling under Chapter 84&72 of the Central Excise Tariff Act,1985 [hereinafter referred as CETA-1985].

2. Brief facts of the case is, during the course of audit by the department it was observed that the appellant had taken and utilized excess service tax credit on security services for the period from July 2012 to February 2014 amounting to Rs.80,004/- .In view of Notification No.30/2012-STdated20.06,2012 as amended vide Notification No. 45/2012-ST Dated 07/08/2012, the service provider was liable to pay service tax @25% of the total service tax payable and the service receiver was required to pay service tax @,75% of the total service tax payable. it was noticed that the service provider had charged service tax @100% of the total taxable value which was in contravention to the Provisions of said Notification, and resulted in excess availment of Cenvat credit of service tax at the receiver's end. the appellant had not paid the service tax 75% ,they were not entitled to avail the input service tax credit @100% . Therefore, the appellant had contravened the provisions of said Notification and Rule 3(1) of the Cenvat Credit Rules, 2004, the provisions of Rule 9(6) ibid, all this contraventions by way of suppression of facts. Therefore ,they were liable for penal action under section11AC(b) of the Central Excise Act 1944 read with Rule 15 [2] ibid. show cause notice was issued, same was decided and confirmed with interest and penalty .

3. Being aggrieved by the above said OIO the appellant filed an appeal on the following main grounds;

They have filed all mandatory returns during the disputed period and shown availment of credit in their monthly returns. That prior to July- 2012,, the service provider was to pay 100% tax. With effect from August-2012 only, the burden has been on recipient of service @75%. The demand in the present case is pertaining to period of July-2012 to feb-2014. When the law is amended it is highly possible that trade may not be aware about the changes in such facts and considering initial period, after the change of guard the penalty may be dropped.

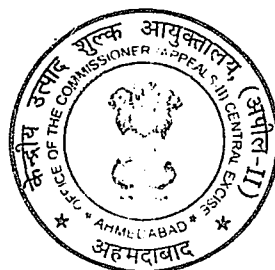


The recipient of service cannot be denied Cenvat Credit. In this regard, the appellant has paid the tax. Relied on following case laws: 1. SARVESH REFRACTORIES (P) LTD vs CCE. reported at 2007 (218) E.L.T. 488 (S.C.) 2. CCE vs MDS SWITCHGEAR LTD. reported at 2008 (229) E.L.T. 485 (S.C.) 3. CCE vs KITCHEN APPLIANCES INDIA LTD reported at 2013 (288) E.L.T. 567. However, it is not disputed that liabilities of duty at the end of provider is not discharged. Reliance placed on following orders:

1. DNS CONTRACTOR vs. CCE Delhi reported at 2015 (37) S.T.R. 848
2. ANGIPLAST P. LTD. VS. CST REPORTED AT 2013 (32) S.T.R. 628

4. Personal hearing was held on 14.06.2016, which was attended by Shri Nirav Shah, Advocate of behalf of the Appellant. He reiterated the grounds of appeal filed by them earlier. he cited judgements 1. SARVESH REFRACTORIES (P) LTD vs CCE. reported at 2007 (218) E.L.T. 488 (S.C.) 2. CCE vs MDS SWITCHGEAR LTD. reported at 2008 (229) E.L.T. 485 (S.C.) 3. CCE vs KITCHEN APPLIANCES INDIA LTD reported at 2013 (288) E.L.T. 567. I have gone through all records placed before me in the form of the impugned order and written submissions of department as well as submissions made during personal hearing. I find that the main issue involved is admissibility of cenvat credit by the appellant on payment of service tax 100% to the service provider. I find that the appellant is the recipient of input service i.e. security service and in terms of Rule 9(1) of the Cenvat Credit Rules, 2004 a challan evidencing payment of service tax, by the service recipient as the person liable to pay service tax is a specified document for taking Cenvat credit. the appellant has continued the practice of availing the credit even after subsequent change in Servicetax rules, reverse charge mechanism as per Notification no.30/2012-ST dated 20.06.2012 as amended read with notification 45/2012-ST dated 07.08.2012, fixed Percentage of service tax payable by the person receiving the service the ratio of 25% and 75% respectively. being a body corporate and recipient of service covered of the said notification at the ratio fixed and then after the payment of service tax by the recipient can be eligible for taking of cenvat credit on the said input service. In the instant case the appellant had availed full cenvat credit on payment of said service tax to the service provider.

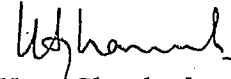
5. I find that the appellant has availed the Cenvat Credit wrongly; said facts came to knowledge of the department on audit. it was noticed



that the Cenvat Credit was taken on the said invalid documents and not discharged their service tax liability according to said Notification. All these acts of contravention on the part of the said assessee appears to have been committed by way of suppression of facts and deliberate contravention of the provisions of Central Excise Rules with an intention to evade payment of Excise duty .therefore, invoking extended period of five years is correct.

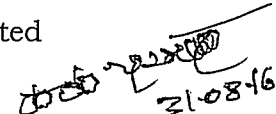
6. In view of above findings, I hold that, the appellant has contravened the provisions of Rules of CCR 2004. They have intentionally taken credit of tax knowing that the same is not admissible. Therefore, the extended period has been correctly invoked. However, the demand in the present case is pertaining to period of July-2012 to feb-2014, when the law was amended, it is highly possible that trade may not be aware about the changes in such facts and considering the initial period, I hold that the penalty imposed is not warranted. Hence it is set aside.

7. In view of foregoing discussion and findings, I uphold the impugned order to that extent, and disallow the appeal. The appeal stands disposed of as above.



[Uma Shanker]
Commissioner (Appeals-II)
Central Excise, Ahmedabad

Attested


31-08-16

(K.K. Parmar)
Superintendent (Appeals-II)
Central excise, Ahmedabad

By Regd. Post A. D

M/s Dhall Enterprises & Engineers Pvt. Ltd.,
Sijpur Bogha, Near G.D. High school,
Naroda Road,
Ahmedabad- 382345

Copy to :

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II.
3. The Asstt Commissioner, Central Excise, Division-II, Ahmedabad-II
4. The Asstt. Commissioner (Systems), Central Excise, Ahmedabad-II.
5. Guard file.
6. PA file.

